



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1992/पौष 8, 1914

No. 526]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1992/PAUSA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

विदेश कर तथा कर अनुसंधान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1992

आयकर

रा.का.नि. 950(अ).—यतः, दो देशों के वायु परिवहन उद्यमों के क्रियाकलापों की आय पर करों की पारस्परिक छूट के द्वारा दोहरे कराधान के परिहार के लिये भारत सरकार तथा मऊदी अरब किंगडम के बीच सम्पूर्ण भुगतान करार, उक्त करार के अनुच्छेद 6 के द्वारा तथा संश्लिष्ट उक्त पत्रों के आदान-प्रदान के जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि प्रत्येक संबिदाकारी राज्य में उचित प्रशिक्षण पूरी की गई थी, साठ दिन बाद 25 दिसम्बर 1992 को लागू हो गया है।

अतः, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 तथा कंपनी (लाभ) अतिकरक अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबन्धों को भारत संघ में प्रभावी बनाया जाये।

अनुबन्ध

भारत गणराज्य तथा मऊदी अरब किंगडम के बीच, दोनों देशों के वायु परिवहन उद्यमों के कार्यकलापों में प्राप्त आय पर करों की पारस्परिक छूट द्वारा दोहरे कराधान के परिहार के लिये करार।

भारत गणराज्य तथा मऊदी अरब किंगडम अंतर्ग्राहीय यातायात में वायु परिवहन के संचालन में उद्यमों तथा उनके कर्मचारियों को प्राप्त आय पर आयद करों की पारस्परिक छूट द्वारा दोहरे कराधान के परिहार के

लिये एक करार सम्पन्न करने की दृष्टि से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं :—

अनुच्छेद—1

परिभाषा

1. इस करार में जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों में, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा मऊदी अरब किंगडम अभिप्रेत है,
- (ख) "कर" शब्द में, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार "मऊदी कर" अथवा "भारतीय कर" अभिप्रेत है ;
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य का वायु परिवहन उद्यम" पद में—

(i) मऊदी अरब के मामले में मऊदी अरब एयर लाइन्स कार्पोरेशन अथवा उसका उत्तराधिकारी ;

(ii) भारत के मामले में एयर इंडिया अथवा उसका उत्तराधिकारी ; अभिप्रेत है ;

(घ) "वायु परिवहन का परिचालन" पद में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा हवाई जहाज द्वारा यात्रियों, असबाब, पशुओं माल-अथवा डाक को लाने—ले जाने का कारोबार करना अभिप्रेत है, जिसमें टिकटों की बिक्री तथा परिवहन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त समरूप इन्सूरेज भी शामिल है ,

(ङ) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद में—एक संविदाकारी राज्य के किसी वायु परिवहन से सम्बद्ध उद्यम द्वारा उसके स्वामित्व के, पट्टे पर लिये गये अथवा अवक्रीत तथा संचालित वायुयान द्वारा किया गया कोई परिवहन अभिप्रेत है सिवाय उस स्थिति के जब ऐसा परिवहन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही किया जाता है ;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" पद में—

(i) भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सरकार ;

(ii) मऊदी अरब के मामले में, वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अभिप्रेत है ;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद में—ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-व्यवस्था का स्थान

अथवा समरूप स्वरूप के किसी अन्य तान्दण्ड के कारण उस राज्य में कर लगाया जा सकता है,

(ज) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई निगम, कोई कंपनी अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है,

(झ) "अन्य अदायगिया" पद में सामाजिक सुरक्षा बीमा, बुढ़ापे की बचत अथवा पेंशन, बीमारी अथवा चिकित्सा बीमा, बेरोजगार बीमा अथवा संविदाकारी राज्य के कानून द्वारा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर आयद आय के अनुपात में की गई नई अन्य अदायगिया अभिप्रेत है ।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा इस करार के उपबन्धों का प्रयोग करने में प्रयुक्त किया शब्द का, जिसे इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित रहे हो, वही अर्थ होगा जो ऐसे करों में संघटित यह राज्य के कानूनों के अन्तर्गत है, जो इस करार का विषय है।

अनुच्छेद—2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य को ओर से आय पर लगाये गये करों पर लागू होगा, भले हो उनको आयद करने का तरीका कुछ भी हो।

2. कुल आय पर, अथवा आय के तत्वों पर लगाये गये सभी करों को आय पर कर के रूप में समझा जायेगा, जिसमें चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाषों पर कर तथा उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों को कुल रकम पर कर भी शामिल है।

3. मौजूदा कर, जिन पर यह करार निर्गम रूप से लागू होगा, निम्नानुसार है :—

(क) भारत के मामले में—

(i) आयकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधिभार भी शामिल है ;

(ii) अतिकर

(जिन्हें एतद्पश्चात् "भारतीय कर" के रूप में उल्लिखित किया गया है) ;

(ख) मऊदी अरब किंगडम के मामले में :

आयकर

(जिसे एतद्पश्चात् "मऊदी कर" के रूप में उल्लिखित किया गया है) ।

4. यह करार किसी समरूप अथवा पर्याप्त रूप से उसी प्रकार के करों पर भी लागू होगा जिन्हें बाद में

इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित करने के अतिरिक्त, अथवा उनके बदले में लगाया जाता हो। सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे को उनके संबंधित कराधान कानूनों में किये गये किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद—3

आय का कराधान

1 एक सविदाकारी राज्य के किसी वायु परिवहन उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये गये वायु परिवहन में प्राप्त आय तथा लाभा को दूसरे सविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2 पैराग्राफ 1 के उपबन्ध एक सविदाकारी राज्य के किसी वायु परिवहन उद्यम द्वारा किसी पक्ष अथवा किसी मयुक्त वायु परिवहन संचालन में उसकी भागीदारी में प्राप्त आय तथा लाभा पर भी लागू होंगे।

3 इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ एक सविदाकारी राज्य के किसी वायु परिवहन उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायु परिवहन के संचालन से प्राप्त लाभों में निम्नलिखित में प्राप्त आय भी शामिल है

(क) दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम को वायुयात अथवा भूमि उपकरण के किराये अथवा पट्टे में प्राप्त आय,

(ख) दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम को प्रशिक्षण यात्राओं, प्रबन्ध-व्यवस्था तथा भी गैर अन्य सेवाओं में प्राप्त आय।

4 पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयात के संचालन में प्रत्यक्षतः संबंध निर्धारा पर व्यापक अथवा उसी समान की आय को वायुयात के संचालन से प्राप्त हुई आय के रूप में समझा जायेगा।

अनुच्छेद—4

वैयक्तिक सेवाओं के लिये पारिश्रमिक

दोनों सविदाकारी राज्यों, उनमें से किसी एक सविदाकारी राज्य के वायु परिवहन उद्यम के किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा पेंशनविवरणों पर, जहाँ-कहीं वे प्राप्त किये गये हों, आयकर अथवा आयकर किये जाने वाले सभी करों तथा अन्य अदायगियों का छूट देन का वायदा करत है, बशर्ते कि वह दूसरे सविदाकारी राज्य का एक नागरिक हो।

अनुच्छेद—5

पारस्परिक करार कार्यविधि तथा विवादों का निपटारा

1 इस करार में संशोधन किये जाने के प्रयोजनार्थ दोनों में से किसी एक सविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय परामर्श करने के लिये अनुरोध किया जा

सकेगा। ऐसा परामर्श, उसके लिये किसी ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख में 90 दिन के भीतर प्रारम्भ होगा।

2 सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उस करार के अर्थनिरूपण में अथवा उसको लागू करने में पैदा होने वाली किसी प्रकार की कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान परस्पर सहमति के द्वारा करेंगे।

अनुच्छेद—6

प्रवर्तन

1 इस करार को प्रत्येक सविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों के अनुसार अनुमोदित अथवा अनुमोदित किया जायेगा। यह करार इस आशय के काराजान के आदान-प्रदान करने के बाद, जिसमें यह प्रमाणित किया जायेगा कि प्रत्येक सविदाकारी राज्य में समुचित कार्यविधि को पूर्ण किया गया, साठ दिन के बाद प्रवृत्त होगा। काराजान का आदान-प्रदान राजनयिक माध्यमों के द्वारा किया जायेगा।

2 इस करार के उपबन्ध जनवरी, 1970 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त की गई आय के संबंध में प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद—7

समापन

यह करार अतिरिक्त काल तक प्रवृत्त रहेगा परन्तु उसे दोना में से किसी भी सविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति में कम से कम छ माह पूर्व समापन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा, उस स्थिति में, यह करार उस कैलेंडर वर्ष के अंत में, जिसमें समापन का नोटिस दिया जाता है, निष्प्रभावी हो जायेगा।

जिसके माध्य में विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरों का उस करार पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उस पर अपनी मोहर लगाई है।

नई दिल्ली में एक हजार तीसरी इकातवे के तबस्वर माह के चौदहवें दिन अर्थात् 8वें जुमादा I, 1412 को हिन्दी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। तीन पाठों में परस्पर भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार सउदी अरब किंगडम की ओर से सरकार की ओर से
डा. मनमोहन सिंह, अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अल-जमील, उद्योग तथा विद्युत मंत्री

[स. 9152फा में 501/6/74-एफ.टी.डी.]

टी एस कृष्ण मूर्ति, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

FOREIGN TAX & TAX RESEARCH

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1992

INCOME-TAX

G.S.R. 950(E).—Whereas the annexed Agreement between the Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia for avoidance of double taxation by reciprocal exemption of taxes on income on the activities of air transport enterprises of the two countries has entered into force on the 25th September, 1992 after sixty days after the exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each Contracting State, as required by Article 6 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BY RECIPROCAL EXEMPTION OF TAXES ON INCOME ON THE ACTIVITIES OF AIR TRANSPORT ENTERPRISES OF THE TWO COUNTRIES

The Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia desiring to conclude an Agreement for Avoidance of Double Taxation by Reciprocal Exemption of Taxes levied on income of enterprises and their employees from operation of air transport in international traffic have agreed as follows :—

Article 1

DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :—

- (a) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean India or the Kingdom of Saudi Arabia, as the context requires;
- (b) the term “tax” means “Saudi tax” or “Indian tax” as the context requires;
- (c) the term “air transport” means the operation of a

(i) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the Saudi Arabian Airlines Corporation or its successor;

(ii) in the case of India, Air India or its successor;

(d) the term “operation of air transport” means the business of transportation by air of passengers, baggage, livestock, goods or mail conducted by an enterprise of a Contracting State including sale of tickets and similar documents used for the purpose of transport;

(e) the term “international traffic” means any transport by aircraft owned, leased or chartered and operated by an air transport enterprise of a Contracting State, except when such transport is made solely between places in the other Contracting State;

(f) the term “Competent authority” means

(i) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia the Ministry of Finance & National Economy;

(ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue;

(g) the term “resident of a Contracting State” means any person, who under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature;

(i) the term “person” includes an individual, a corporation, a company or any other body of persons;

(ii) the term “other payments” means social security insurance, old age annuity or pension, sickness or medical insurance, unemployment insurance or any other payments measured by income levied on the salaries and allowances of the employees by the law of the Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term used but not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular;

- (a) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia the income-tax, (hereinafter referred to as "Saudi Tax");
- (b) in the case of India :
 - (i) the income-tax including any surcharge thereon;
 - (ii) the sur-tax (hereinafter referred to as "Indian Tax").

4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes as are subsequently imposed in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

TAXATION OF INCOME

1. Income and profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State from the operation of air transport in international traffic shall be exempted from tax in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income and profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State from its participation in a pool or a joint air transport operation.

3. For the purposes of this Article, profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State, from the operation of air transport in international traffic also include income derived from :

- (a) the rental or lease of aircraft or ground equipment to the enterprise of the other contracting State;
- (b) training schemes, management and other services rendered to the enterprise of the other Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 1, interest or similar earnings on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of aircraft.

Article 4

REMUNERATION FOR PERSONAL SERVICES

The two Contracting States undertake to extend exemption of all taxes and other payments levied or to be levied on salaries, wages, allowances and perquisites, wherever received, by an employee belonging to the air transport enterprise of either Contracting State provided that he is a citizen of the other Contracting State.

Article 5

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE AND SETTLEMENT DISPUTES

1. Consultation may be requested at any time by either Contracting State for the purpose of amendment to this Agreement. Such consultation shall begin within 90 days from the date of receipt of any such request.

2. The competent authorities of the Contracting States shall resolve by mutual agreement any difficulties or doubts regarding the interpretation or application of this Agreement

Article 6

ENTER INTO FORCE

1. This Agreement shall be approved or ratified in accordance with the laws in force in each of the Contracting States. It shall enter into force sixty days after the exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each Contracting States. The exchange of letters shall be through diplomatic channels.

2. The provisions of this Agreement shall have effect in respect of income derived on or after the 1st day of January 1970.

Article 7

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but may be terminated by either Contracting State by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year, in which case, this Agreement shall cease to have effect from the end of the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF THE undersigned duly authorized thereto, have signed this Agreement, have affixed thereto their seal

Done at New Delhi this 14th day of November, 1991, corresponding to 8th Jumada I, 1412, in two originals, in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Dr. Manmohan Singh,
Minister of Finance

Abdul Aziz Abdullah Al-Zamil
Minister of Industry and
Electricity

[No. 9152 F. No. 501/6/74-FTD]
T. S. KRISHNA MURTHY, Jr. Secy.

